कृषि विकास में विविधता, बंजर भूमि विकास और वृक्ष लगाना, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्रक और ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास, लघु और विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्र वृद्धि और आवास सुविधाओं का विस्तार योजना में दर्शाई गई रोजगार पर आधारित विकास नीति के मूल घटक हैं। इस योजना में प्रतिवर्ष औसतन 8 से 9 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए जाने की संभावना है। यह अनुमान है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बेरोजगारी का बैकलॉग लगभग 10 मिलियन होने की संभावना है जबकि योजना के आरम्भ में यह 17 मिलियन थी। प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित अथवा शिक्षित/अशिक्षित युवा, जिन्हें आठवीं योजना के अंत में नौकरी उपलब्ध करा दी जाएगी और जो बेरोजगार रह जाएंगे, के संबंध में अलग अनुमान नहीं लगाए गए हैं।

आठवीं योजनावधि के दौरान जनता का सहयोग

1845. **श्री विनोद शर्मा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि इसके प्रथम वर्ष के दौरान देश के 150 ब्लाकों में स्थानीय जनता के सहयोग से विकास योजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जून, 1992 तक उन सभी 150 ब्लाकों का पता लगा लिया है जहां, इन योजनाओं को आरम्भ किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग ऐसे ब्लाकों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन ब्लाकों में ये योजनाएं किस महीने से कार्यान्वित की जाएंगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां, आठवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान लोगों तथा जन संस्थाओं की पूर्ण भागीदारी से माइक्रो स्तरीय सहभागिता आयोजना को 150 ब्लाकों में बतौर प्रयोग शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) स्कीमों को अगस्त, 1992 के मध्य तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है, जिसके बाद मुख्यमंत्रियों से परामर्श किया जाएगा तथा ब्लाकों की पहचान की जाएगी। इसके बाद कार्यान्वयन शुरू होगा।

गरीबी कम करने में विदेशी सहायता की विफलता

1846. **श्री राम जेठमलानी** :
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जून, 1992 के "दि इकानोमिक टाइम्स" में "फोरेन एड फेल्ड टु हैल्प इंडिया रिमूव पावर्टी, सेज स्टडी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वाशिंगटन स्थित काटो संस्थान ने भारत में गरीबी उन्मूलन की दिशा में पर्याप्त प्रगति न होने का आरोप लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है;

(घ) क्या इस अध्ययन प्रतिवेदन में केन्द्रीय योजनाओं में परिवर्तन करने के सुझाव भी दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सरकार को दिनांक 20 जून, 1992 के इकानोमिक टाइम्स के "फोरेन एड फेल्ड टु हैल्प इंडिया रिड्यूस पावर्टी, सेज स्टडी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार के बारे में पता है। लेकिन प्रश्न में उद्धत शीर्षक भिन्न है।

(ख) वाशिंगटन आधारित काटो संस्थान, एक अनुसंधान संगठन, के नीति विश्लेषण पेपर में प्रकाशित अध्ययन में, जैसा कि समाचार पत्र में बताया गया है, उस संस्थान के एक विद्वान के भारत में विकास की प्रवृत्ति तथा प्रक्रिया के बारे में निजी विचार हैं, जिसमें विद्वान महोदय को काफी दोष दिखाई देता है।

(ग) भारत में विकास की प्रवृत्ति तथा प्रक्रिया पर सरकार भारतीय संसद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के विचारों से मार्गदर्शन प्राप्त करती रहेगी।

(घ) और (ङ) समाचार का उद्धरण संलग्न विवरण में दिया गया है

विवरण

अध्ययन के अनुसार विदेशी सहायता भारत की गरीबी कम करने के लिए मदद करने में असमर्थ

इंडिया एब्रोड न्यूज सर्विस
हवार्ड 19 जून

एक अध्ययन के अनुसार पिछले चार दशकों में भारत सबसे बड़ी अमरीकी और बहुपक्षीय सहायता प्राप्त विदेशी सहायता कार्यक्रमों के प्राप्तकर्ताओं में से एक है लेकिन गरीबी दूर करने में अथवा आर्थिक वृद्धि बढ़ाने में विफल रहा है ।

वाशिंगटन स्थित केटो संस्थान के नीति विश्लेषण प्रलेख के हाल ही के अंक में प्रकाशित किया गया यह अध्ययन उत्तर केलिफोर्निया में हवार्ड स्थित केलिफोर्निया राज्य विश्वविद्यालय के बिजनेस और इकानामिक्स स्कूल में इकानामिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर श्री श्याम जे० कामथ द्वारा किया गया था ।

नीति विश्लेषण सरकारी नीतियों का मूल्यांकन करने वाला और सुधार के लिए प्रस्ताव सुझाने वाली नियमित श्रृंखला है ।

वर्तमान बहस में कि क्या अमरीका कर दाताओं द्वारा वित्तपोषित विदेशी सहायता के आगामी कार्यक्रम शीत-युद्ध समाप्ति के बाद के युग में औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं, इस अध्ययन का और अधिक महत्व हो जाता है ।

श्री कामथ का कहना था कि भारत ने 1951 में इसकी पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ होने के बाद से अन्य किसी विकासशील देश की तुलना में अधिक विदेशी सहायता प्राप्त की है । भारत ने अनुमानत: 55 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त किए हैं ।

लेकिन, उनका कहना था कि, वित्तीय सहायता प्राप्त करने और केन्द्रीकृत आयोजना के 45 वर्ष बाद भी भारत में न्यूनतम वृद्धि दर है और सर्वाधिक गरीब देशों में से एक बना हुआ है ।

श्री कामथ ने बताया कि केवल 1988–89 में 222 बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से 101 में घाटा हुआ और अमरीकी बजट घाटे की तुलना में पांच गुना केन्द्रीय घाटा हुआ ।

अपने प्रलेख में श्री कामथ ने बताया कि 20 मिलियन से अधिक भारतीय पब्लिक पे-रोल पर थे, भारत का घाटा पांच गुना अधिक था, इसकी वार्षिक प्रति

व्यक्ति आय लगभग 300 डालर रही और 40 प्रतिशत से सभी अधिक भारतीय गरीबी रेखा से नीचे रहे ।

न केवल भारत की केन्द्रीयकृत आयोजना बल्कि 1950 के बाद विश्व बैंक की ऋण देने की नीतियों की भी आलोचना करते हुए प्रो० कामथ ने लिखा कि विश्व बैंक की भारत, तंजानिया, इथीयोपिया और मेक्सिको जैसे देशों में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं के कारण वह निराशाजनक स्थिति आई ।

प्रो० कामथ टिप्पणी करते हैं, भारत ने सर्वाधिक विश्व बैंक सहायता प्राप्त की— 1951 से 1989 तक 20 बिलियन डालर से भी अधिक, जिसका अधिकतर भाग सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को मिला ।

विदेशी सहायता प्राप्त करने की एक पूर्व शर्त के रूप में सरकारों द्वारा व्यापक विकास योजना आरंभ करवाते हुए दाता राष्ट्रों और विश्व वित्तीय एजेंसियों ने विकासशील देशों के समाजीकरण को सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया, लेखक का यह निष्कर्ष था ।

श्री कामथ के अनुसार अमरीकी सहायता ने सरकारी उपक्रमों की जिम्मेवारी ली, अमरीकी सहायता का एक बड़ा भाग 1955 से 1971 तक दिया गया और 1951 से 1985 तक 5 प्रतिशत से भी कम निजी क्षेत्रों को दिया गया ।

उनकी टिप्पणी थी कि वाशिंगटन सहायता से सरकारी उर्वरक और औद्योगिक संयंत्रों, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं, सरकार के स्वामित्व वाली विद्युत परियोजनाओं, राजमार्गों का निर्माण, सरकारी रेलवे प्रणाली के लिए लोकोमोटिव और रोलिंग स्टाक, को वित्त पोषित किया गया और एक महत्वपूर्ण भाग था खाद्य सहायता ।

उन्होंने स्वीकार किया कि सहायता की कथित सफलता के कुछ मामले रहे थे जैसे 1950 के दशक के आरंभ में और फिर दुबारा 1960 के दशक के मध्य में लाखों लोगों के भुखमरी के कगार पर होने पर महत्वपूर्ण खाद्य सहायता ।

उन्होंने कहा, अन्यथा, भारत को दी गई सहायता कम त्रासदी नहीं थी । यदि निजी क्षेत्र की कीमत पर सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि को जाती है तो विदेशी सहायता विकास अर्थव्यवस्था के पुराने और झूठे सिद्धांत, कि आर्थिक विकास के लिए केवल पूंजी और प्रौद्योगिकी तक अभिगम्यता की आवश्यकता होती है, पर आधारित रही थी और अब भी जारी है ।

वे कहते हैं, आवश्यकता है केन्द्रीय योजना प्रणाली को खत्म करने की, अकुशल सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े पैमाने पर निजीकरण को, विदेशी व्यापार और बाहरी क्षेत्र के नियंत्रण को पूरी तरह से खत्म करना, निजी पूंजी और स्वैच्छिक एक्सचेंज तक पूर्ण अधिकार का नियमन और बहाली ।

Meaning of rationalisation of labour

1847. SHRI SOM PAL:
SHRI SARADA MOHANTY:
SHRIMATI MIRA DAS:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 79 given in the Rajya Sabha on 13th July, 1992 and state the meaning of rationalisation of labour, and what is the number of surplus staff in National Textiles Corporation mills and its percentage to total strength?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): Rationalisation of labour would mean optimisation of manpower to maximise productivity and efficiency within the parameters of technical feasibility and economic viability. 7,116 out of 14,952 or about 52 per cent of the officers and staff of NTC would be rendered surplus if the Turnaround strategy proposed by NTC were to be implemented.